

समलैंगिकता और न्यायालय का निर्णय

हजारो वर्ष से यह बहस चली आ रही है कि व्यक्ति और समाज के बीच व्यक्ति स्वातंत्र और सामाजिक नियंत्रण के बीच का अनुपात क्या है और उसकी सीमा रेखा क्या हो? समाज के लोग व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलो मे नैतिकता की दुहाई देकर अधिक नियंत्रण करना चाहते है जबकि व्यक्ति ऐसे नियंत्रण को तोड कर अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है । व्यक्ति की कामवासना पूर्ति इस सीमा रेखा निर्धारण मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। या यूँ कहे कि व्यक्ति और समाज के बीच टकराव मे इस प्रवृति का सबसे अधिक योगदान रहता है तो कोई अतिषयोक्ति नही होगी।

व्यक्ति की कामवासना की पूर्ति का सबसे अच्छा माध्यम स्त्री और पुरुश के बीच आपसी संयोग को माना जाता है । इस से अच्छा कोई अन्य आधार इसलिये नही है कि इससे एक ही क्रिया से दो लोगो की इच्छा पूर्ति हो जाती है तथा आवश्यकता अनुसार सन्तानोत्पत्ति के द्वारा श्रृष्टि का विस्तार होता रहता है जो किसी और माध्यम से संभव नही है। स्त्री पुरुश के बीच की इस क्रिया को व्यवस्थित और संगठित स्वरूप देने के लिए समाज ने विवाह के नाम पर एक व्यवस्था बनाई है। और इस तरह विवाह के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक छूट प्राप्त इस क्रिया को पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता है । पति पत्नी के संबंधो के अतिरिक्त होने वाली इस क्रिया को असामाजिक अवैध और अनैतिक मानकर अनुचित धोशित किया गया है। यदि यह क्रिया स्त्री पुरुश के बीच बिना सहमति के बल पूर्वक की जाती है तो उसे समाज विरोधी कार्य या गंभीर अपराध मानकर राज्य द्वारा दण्डित कराने की व्यवस्था बनी हुई है।

स्त्री पुरुश के बीच होने वाली इस क्रिया के अतिरिक्त कामवासना के जो भी माध्यम होते है वे सब अनैतिक असामाजिक और अवांछनीय माने जाते है। इन क्रियाओ मे समलैंगिकता या पशु उपयोग या अन्य प्रकार की क्रिया शामिल हैं। ऐसी सब प्रकार की क्रियाओ को समाज मे एक बुरा कार्य माना जाता है यधपि बलप्रयोग न होने के कारण ये क्रियाए अपराध की श्रेणी मे हो या न हो इस पर बहस चलती रहती है। आज के तथा कथित समाज षास्त्री इन अवैध क्रियाओ को अपराध धोशित कराने के लिए लगातार प्रयत्न षील रहते है तथा तथाकथित मानवतावादी लोग इसे व्यक्ति स्वातंत्र का नाम देकर इन अवैध क्रियाओ को वैध कराने का प्रयत्न करते रहते है।

प्राचीन समय में बलात्कार के अतिरिक्त अन्य सभी वैध अवैध कामक्रियाओं को राज्य हस्तक्षेप से दूर रखा जाता था और समाज इन को प्रोत्साहित निरूत्साहित करता रहता था। किन्तु सौ डेढ़ सौ वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड की राज्य व्यवस्था को यह भ्रम हुआ कि राज्य ही समाज का एकमात्र वैध प्रतिनिधि है इसलिए राज्य को यह अधिकार है कि वह समाज की हर अनुचित गति विधि के विषय के कानून बनावे भले ही वह गतिविधि अपराध केश्रेणी में आवे या न आवे और ऐसा मानकर राज्य ने बलात्कार के साथ साथ समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी में शामिल कर लिया और उसके लिए दण्ड का प्रावधान कर दिया। वही से यह बहस शुरू हुई कि अप्राकृतिक मैथुन अपराध होना चाहिए कि नहीं। इस संबंध में पशु या अन्य कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे लेकिन मनुष्य ने समलैंगिकता के कानून से बचने की आवाज जारी रखी। भारतीय संविधान निर्माताओं की अपने स्वयं की सोच तो कुछ थी नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद इंग्लैण्ड की नकल की और उसके अच्छे या बुरे प्रावधानों को जारी रखा। कुछ वर्ष पहले इंग्लैण्ड ने अपने कानूनों में समलैंगिकता के संबंध में संशोधन कर दिया किन्तु भारतीय कानून व्यवस्था समाज की नैतिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे संशोधन से सहमत नहीं हुई और इसी कारण भारत में बहस चलती रही। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका में निर्णय देते हुए समलैंगिकता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वीकार करते हुए उसे वैध धोशित कर दिया। सरकार में भी इस विषय पर गंभीर सोच विचार चल रहा था तभी कोर्ट का निर्णय आ जाने से यह मामला गंभीर विचार मंथन का मामला बन गया। सभी प्रकार के धर्म शास्त्री न्यायालय के विरुद्ध मैदान में आये। ईसाई धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु तो इसके विरोध में थे ही, हिन्दु धर्म गुरुओं ने भी एक स्वर से इस कानूनी संशोधन का विरोध करना शुरू कर दिया इस विरोध के स्वर में उन संस्थाओं के प्रमुख लोग भी बढ़ चढ़ कर हल्ला करने लगे जिन संस्था में विवाह की अनुमति न होने के कारण समलैंगिकता मजबूरी के रूप में बड़ी मात्रा में उपयोग में आती रहती है। देश के कई अच्छे अच्छे ख्याति प्राप्त सामाजिक या राजनैतिक प्रमुखों के बारे में गुप्त रूप से ऐसा करने की बात आम लोग जानते हैं। फिर भी इस अनैतिक कार्य को नैतिक मान लिया जाये इसके लिये भारत का आम जनमानस तैयार नहीं हुआ। इसलिये यह बहस ज्यादा गंभीर हो गई कि समलैंगिकता को नैतिक धोशित किया जाये या अपराध की श्रेणी में रखा जाये।

पचासो वर्षों से मेरा स्पष्ट मत रहा है कि विवाहेतर यौन क्रिया अनैतिक कार्य है। उसमें समलैंगिकता भी शामिल है। इस अनैतिक कार्य को नैतिकता

का जामा पहनाना सर्वथा अनुचित है। स्त्री पुरुष की आपसी संबंधो के अतिरिक्त अन्य यौन क्रियाये नैतिक मानी ही नहीं जा सकती। स्त्री पुरुष के संबंधो मे भी पति पत्नी के संबंधो को छोड कर अन्य योन क्रिया अनैतिक ही है। इस आधार पर मेरा स्पष्ट मत है कि समाज द्वारा स्वीकृत विवाह के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की योन क्रिया को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है बल्कि निरूसाहित ही करना चाहिए । समलैंगिकता को प्रोत्साहित करने वाले या वैध धोशित कराने वाले पूरी तरह असामाजिक दिषा मे प्रयत्न षील है। मै ऐसे प्रयत्नो के विरूध हूँ दूसरी और बलात्कार को छोडकर सभी प्रकार की यौन क्रिया अनैतिक तो हो सकती है किन्तु अपराध नहीं। कानून के द्वारा ऐसे अनैतिक कार्य को रोकने का समर्थन करने वाले लोग या तो नासमझ है या असक्षम है। जिन धर्म प्रमुखो का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, जिनके प्रयत्नो से समाज मे नैतिकता विस्तार पर कोई असर नहीं पड रहा है। वे अपने आभा मण्डल को बनाये रखने के लिए ऐसे कार्यो पर रोक लगाने मे कानून का सहारा लेने का प्रयत्न करते रहते है । सच्चाई यह है कि ऐसे धर्माचार्य ही समाज को राज्य का गुलाम बनाकर रखने की पृष्ठ भूमि बनाते रहते है। मुस्लिम धर्म गुरुओ की चर्चा व्यर्थ है क्योकि वे तो राज्य , धर्म, समाज, का अन्तर ही नहीं समझते है किन्तु हिन्दू धर्म गुरु भी इस राह पर चलने लगते है तो कष्ट होता है। समलैंगिकता अनैतिक है और निरूत्साहित करना चाहिए । किन्तु यह कार्य राज्य का नहीं समाज का है। राज्य के द्वारा समाज के कार्यो मे हस्तक्षेप हमेषा समस्या पैदा करता है। इस मामले मे ऐसा हो रहा है इसलिये मेरा मत है कि समलैंगिकता के कानून के विरोध मे न्यायालय ने निर्णय दिया है वह पूरी तरह तर्क संगत है। इससे सामाजिक षक्ति मजबूत होगी किन्तु न्यायालय के इस निर्णय को समलैंगिकता का साथ मानना एक बडी भूल होगी और इस भूल से बचा जाना चाहिए। समलैंगिकता अनैतिक है, अनुचित है, अपराध नहीं।

समलैंगिकता के सम्बध मे मेरे पूर्व विचार मैने व्यक्त किये है मैने बहुत वर्शो की सोच के अनुरूप व्यक्त किये है । महिला और पुरुष को अलग अलग न मानकर एक सयुक्त ईकाई के रूप मे मानता रहा हूँ। मैने वैस्यावृति तक को अपराध नहीं माना और उसे अनैतिक कार्य मानकर अपराध से अलग करने का सुझाव दिया था। महिला और पुरुष के बीच के संबंधों पर मैने ज्ञान तत्व 143 मे 2 लेख लिखा था जो इस अंक मे फिर से दिया जा रहा है। जिससे इस गंभीर विचार मंथन के क्रम मे मेरे विचार स्पष्ट हो सके लेख इस प्रकार है।

महिला सशक्तीकरण कितनी समस्या कितना समाधान

समाज में शराफत और धूर्तता के बीच हमेशा ही टकराव रहा है। शरीफ लोगो की औसत संख्या अटान्ने प्रतिषत और अपराधी धूर्तो की दो के आस पास होती है। ये दो प्रतिषत लोग स्वय को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वर्ग निर्माण का सहारा करते है। यह वर्ग निर्माण ऐसे तत्वो को छिपने के भी अवसर प्रदान करता है और अटान्ने प्रतिषत लोगो को कई वर्गो मे बाटकर उनमे आपसी वर्ग संघर्ष कराने के भी अवसर पैदा करता है। अपराधियो की यह चालाकी हजारो वर्शो से चली आ रही है और आज तो और भी तीव्र गति से बढ रही है भले ही उसका स्वरूप कुछ बदल गया हो।

समाज के प्राकृतिक स्वरूप मे महिलाओ की आबादी लगभग पचास प्रतिषत मानी जाती है। समाज विस्तार के लिए महिला और पुरुश की एकाकार जीवन सहभागिता अनिवार्य होती है जिसे परिवार कहते है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच परिवार एक अनिवार्य कडी के रूप में है जिसे व्यवस्था से बाहर करना संभव नही। व्यवस्था के तीन अंग होते हुए भी यह आवश्यक है कि तीनो का अपना – अपना अस्तित्व भी बना रहे और तीनो का सामूहिक अस्तित्व भी। यही एक जटिल कार्य है जिसे व्यवस्था कहते है और वह व्यवस्था तोडकर वर्ग निर्माण करने का अपराधियो का प्रयत्न हमेशा जारी रहता है।

महिलाओ की शारीरिक संरचना और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर स्वाभाविक कार्य विभाजन मे व्यवस्था मे पुरुश की भूमिका मुखिया की रही है। धूर्तो ने इस मुखिया की भूमिका को मालिक की भूमिका मे बदलकर महिलाओ को एक गुलाम वर्ग के रूप मे स्थापित किया। महिलाओ के समान अधिकारो मे कटौती की गई। कार्य विभाजन मे भी कही भी महिलाओ के साथ असमानता नही थी लेकिन अधिकार विभाजन मे पुरुशो ने भेदभाव शुरु कर दिया। परिवार मे सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार किया गया कि उसमे से महिलाओ को बिल्कुल बाहर कर दिया जावे। सबसे सरल और और स्वाभाविक सम्पत्ति विभाजन परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्पत्ति मे समान अधिकार होता किन्तु उसे बहुत जटिल बनाकर पुरुशो ने अपना एकाधिकार बनाने का प्रयत्न किया। इस्लामिक समाज व्यवस्था ने तो इससे भी आगे बढकर महिलाओ की गवाही को ही पुरुशो से आधे महत्व की मान लिया और रही सही कसर तलाक के एक पक्षीय पुरुश अधिकार ने पूरी कर दी। पुरुशो ने अधिकार विभाजन मे अपने को एक वर्ग के रूप मे स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया।

इसके धातक परिणाम होने ही थे। पुरुश और महिला दो वर्ग के रूप में स्थापित होने लगे । दोनो के बीच षोशक और षोशित की पहचान बनने लगी। महिलाओं में हीन भाव और पुरुशों में उच्च भाव बढ़ा। ऐसे समय में समाज के षुभचिन्तकों ने महिला पुरुश समानता की आवाज उठाई जो स्वाभाविक भी थी और उचित भी। इस समान अधिकार के लिए समाज में सोच भी बढ़नी षुरू हुई थी। स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी आदि ने पुरुशों की सोच बदलने का प्रयास किया जिसके अच्छे परिणाम आने षुरू हुए। अपराधी तत्वों को चिन्ता हुई। उन्होंने समान अधिकार के लिए सामाजिक प्रयत्नों में सहयोग के विपरीत महिलाओं को विशेष अधिकार दिलाने का आंदोलन षुरू किया। महिलाओं को संगठित किया जाने लगा। महिलाओं को पुरुशों के विरुद्ध वर्ग के रूप में अधिकार जागरूक किया जाने लगा। महिला जागृति आंदोलनों से महिलाओं पर पुरुशों का अत्याचार कम हुआ। किन्तु समाज व्यवस्था भी कमजोर हुई और परिवार व्यवस्था भी। सबसे बड़ा खतरा यह पैदा हुआ कि समाज व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और बढ़ते-बढ़ते उसने एक समस्या का रूप ले लिया।

राजनैतिक कानूनी हस्तक्षेप के आधार पर महिलाओं को विशेष अधिकार दिये जाने लगे। दहेज, बाल विवाह, पारिवारिक हिंसा, महिला उत्पीडन आदि के नाम पर नये-नये कानून बनने लगे। महिला सषक्तीकरण के नाम पर उन्हें वर्ग के रूप में विशेष अधिकार दिये जाने लगे। दहेज या बलात्कार जैसे मामलों में उसकी गवाही को विशेष महत्व दिया जाने लगा। धूर्त महिलाएँ ऐसे विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करने लगीं और धीरे धीरे धूर्त पुरुश भी ऐसी महिलाओं को आगे करके षरीफ परिवारों के विरुद्ध अत्याचार करने लगे। दहेज के नाम पर अनेक परिवारों को मामूली प्रकरणों में गंभीर यातनाएं भोगनी पड़ी। मैं ऐसे अनेक प्रकरण व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हमारे क्षेत्र की महिला अधिकारी को एक वरिष्ठ नेता ने किसी बात पर ट्रान्सफर कराने की धमकी दी। उस अधिकारी महिला ने उक्त नेता को कहा कि , सुन रे नेता, तुम तो पता नहीं कुछ कर सकेगा या नहीं किन्तु मैं तो तुझे लम्बे समय तक तुरन्त ही जेल में रहने की व्यवस्था कर सकती हूँ। तेरी जमानत भी नहीं होगी। मैं आदिवासी भी हूँ और महिला भी। साथ में अविवाहित भी हूँ। एक बार चिल्ला देना ही तेरे लिए काफी है, क्योंकि तुम अभी मेरे घर में बैठे हो । मेरे घर के पडोस के एक आत्महत्या के प्रकरण को दहेज के साथ जोडने के झूठे प्रयास के मुकदमें का निर्णय करने वाले न्यायाधीष ने स्वयं ही अफसोस व्यक्त करते हुए मुझे बताया कि पूरा प्रयास

करने के बाद भी वह उक्त प्रकरण में सजा नहीं दे सका इसका उसे मलाल है। अन्यथा वह तो महिला उत्पीडन के प्रकरण छोड़ता ही नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व एक धूर्त ने अपने दामाद पंकज और उसके पूरे परिवार को दहेज हत्या के आरोप में जेल भिजवा दिया। बाद में उसने अपनी लडकी का विवाह नोयडा के प्रभात कुमार के साथ कर दिया। ये दोनों पति पत्नी नया घर बसा कर रहने लगे और उसका पूर्व पति और उसका परिवार दहेज हत्या के जुर्म में जेल काटने लगा। मैंने अपने क्षेत्र के आस पास सर्वे करके पाया कि धूर्त लोग झूठे दहेज प्रकरणों का सहारा लेना बहुत सुविधाजनक समाधान मानने लगे है।

मैं प्रारम्भ से ही इस विचार का रहा हूँ जिसमें महिलाओ को एक वर्ग के रूप में स्थापित करना या मजबूत करना अनावश्यक भी है और घातक भी। मैंने हमेशा ही महिला आरक्षण को इस आधार पर एक शड्यंत्र माना कि इससे रोजगार या राजनीति का कुछ सक्षम परिवारों के बीच केन्द्रीयकरण होगा अर्थात यदि एक सौ रोजगारों में पहले साठ परिवारों के लोग शामिल थे तो अब महिला आरक्षित रोजगार व्यवस्था में वह संख्या तैंतालीस परिवारों तक सिमट जायेगी। यही हाल राजनीति का भी होने वाला है। यही कारण है कि सक्षम परिवारों तथा बुद्धिजीवी अवसरों के ही लाभ प्राप्त लोग आरक्षण की आवाज लगाने में आगे-आगे हैं। न तो अक्षम लोग आरक्षण की आवाज में शामिल हैं न ही श्रम प्रधान रोजगार के लिए ऐसी कोई माग उठ रही है। गरीबी या श्रम प्रधान रोजगार के विरुद्ध राजनीतिक षक्ति या सरकारी नौकरियों की छीना-झपटी में महिला आरक्षण के नाम पर अपने परिवार के लिए कुछ अधिक बटोर लेने का नाम ही महिला सषक्तिकरण हो गया है।

मैं मानता हूँ कि हजारों वशों की समाज व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में संषोधनों की आवश्यकता है। इन संषोधन के लिए महिला समानता के सामाजिक प्रयत्नों के साथ साथ कुछ कानूनी प्रयत्न भी आवश्यक है। इनमें महिलाओं को पारिवारिक सम्पत्ति में समान अधिकार एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे आज तक न लागू किया गया न मांग उठी हैं। किन्तु मैं महिला सषक्तिकरण के लिए कानूनों द्वारा विषेश अधिकार दिये जाने को घातक मानता हूँ।

समाज व्यवस्था की कमजोरियों ने समाज में सामाजिक अन्याय पैदा किया है यह सच है। किन्तु सामाजिक कमजोरियों के जितने दुश्परिणाम

हजारों वशों के बाद दिखे हैं उससे अधिक दुश्परिणाम कानूनी व्यवस्था में पचास वर्षों में ही दिखने लगेंगे। कानूनी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की सहायक तो हो सकती है किन्तु विकल्प बनाने का प्रयास घातक होगा। साम्यवादी और पूंजीवादी विदेशी संस्कृतियां भारत की परिवार व्यवस्था पर लगातार आक्रमण कर रही हैं। महिलाओं को वर्ग के रूप में स्थापित करना उनके लिए बहुत सुविधाजनक है और इस कार्य के लिए सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर कानूनी व्यवस्था की स्थापना उनके लिए बहुत आसान मार्ग है। सबसे अधिक कष्ट कारक स्थिति तो यह है कि इन विदेशी परिवार तोड़क विचारों ने भारतीय सामाजिक संस्थाओं में भी अपने धन या अन्य प्रलोभनों के द्वारा घुसपैठ बना ली है। ये सामाजिक संस्थाएं भी समाज की सामाजिक कमियों को दूर करने की अपेक्षा इसके लिए कानूनी हस्तक्षेप का आह्वान करती हैं। ये संस्थाएं समाज को अधिक गुमराह कर रही हैं।

मैं इस लेख के द्वारा समाज को सतर्क करना चाहता हूँ कि समाज व्यवस्था की अपेक्षा राजनैतिक व्यवस्था कम टिकाऊ भी होगी और अधिक घातक भी। यदि समाज व्यवस्था में विकृतियां हजारों वशों में आई हैं तो राजनैतिक व्यवस्था दस-बीस वशों में ही विकृत हो जाएगी। राजनीति से जुड़े लोग बहुत तेज गति से सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण करने की लूट में लगे हुए हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक न्याय की दिशा में कितना बढ़ा सकेंगे यह तो निश्चित पता नहीं किन्तु समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था को इतना क्षत-विक्षत कर देंगे कि हम लम्बे समय तक उसके दुश्परिणाम भोगते रहेंगे। इसलिए समाज को इस संबंध में सावधानी पूर्वक कदम उठाना चाहिए।

आमंत्रण

25 दिसम्बर 2008 को मैंने व्यवस्था परिवर्तन ट्रस्ट को स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था और घोशणा की थी कि ट्रस्ट के निर्देशन में भविष्य में काम करूंगा। उस दिन मैंने सभी प्रकार के धन, पद, या अन्य संबंधों से भी मुक्त मानने की घोशणा की थी। मेरी घोशणा के बाद ट्रस्ट ने एक बैठक करके नई व्यवस्था होते तक मुझे इसी तरह काम करते रहने की सलाह दी थी। तदनुसार दो प्रकार के संगठन वर्तमान में कार्यरत हैं 1. लोक स्वराज्य अभियान 2. ज्ञान यज्ञ परिवार । दोनों का संगठन का ढांचा

अलग-अलग है तथा कार्य प्रणाली भी अलग-अलग है। लोक स्वराज्य अभियान लोक तंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से लोक नियंत्रित तंत्र में बदलने का अभियान चला रहा है। तथा ज्ञान यज्ञ परिवार ज्ञान तत्व विस्तार में लगा हुआ है जिसका आषय है प्रत्येक ब्यक्ति में ज्ञान का विस्तार करना ।

समाज में दो प्रकार के लोग है 1. बुद्धि प्रधान 2. भावना प्रधान। बुद्धि प्रधान लोग लोक स्वराज्य अभियान से ज्यादा जुड रहे हैं जो षासन मुक्ति की दिषा में आंदोलन की राह पर चल रहा है। ज्ञान यज्ञ परिवार के साथ भावना प्रधान लोग अधिक जुड रहें है जो समाज सषक्ति करण की दिषा में चल रहें हैं। समाज सषक्त तभी होगा जब प्रत्येक ब्यक्ति के स्वयं सोचने की ताकत बढेगी । इस कार्य के लिए 1सितम्बर से दोनो दिषाओं में अलग-अलग अभियान षुरू किया जा रहा है। लोक स्वराज्य अभियान का विस्तृत कार्यक्रम आपको सेवा ग्राम कार्यालय या दिल्ली कार्यालय से मिलता रहता है। ज्ञान यज्ञ परिवार का कार्यक्रम आपको अम्बिकापुर कार्यालय से भेजा जा रहा है। दिनांक 29 एवं 30 अगस्त को दिल्ली के निकट नोएडा अग्रसेन भवन सेक्टर 33 प्रकाष हास्पीटल के पास में ज्ञान यज्ञ परिवार की एक बैठक या सम्मेलन आयोजित है जिसमे पूरे देश से अपने लोगोंको षामिल होना चाहिए। इस सम्मेलन में पहले दिन 29 तारीख को तीन सत्र रखे जाएगे पहला सत्र 9.30बजे से 1बजे तक चलेगा जिसमें ज्ञान यज्ञ की विधि पर पूरी चर्चा होकर होगी दूसरा सत्र 2.30 बजे से षुरू जो 4.30बजे तक चलेगा इस सत्र में ज्ञान यज्ञ के संगठन संबंधी चर्चा होगी तीसरा सत्र 5बजे से 8 बजे तक चलेगा इस सत्र में ट्रस्ट की वैठक होगी दूसरे दिन 30 अगस्त को सुबह 8.30 बजे से 1बजे तक देश भर में होने वाले ज्ञान यज्ञों की रूपरेखा बनेगी 2.30 बजे से 5बजे तक लोक स्वराज्य अभियान की बैठक होगी और 5 बजे के बाद मेरा समापन भाशण होगा मेरा समापन भाशण होने के बाद सम्मेलन समाप्त हो जाएगा।

यह सम्मेलन मुख्य रूप से ज्ञान यज्ञ परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत है फिर भी एक एक सत्र ट्रस्ट एवं लोक स्वराज्य अभियान के लिए भी रखा गया है। इन दो दिनों के सम्मेलन में सैद्धान्तिक चर्चा न करके सिर्फ योजनाओं पर चर्चा करनी है इस लिए प्रत्येक सत्र में सैद्धान्तिक चर्चाओं तथा बहस से बचा जाएगा। 25 दिसम्बर के बाद अब कार्य षुरू करने का समय आ गया है इसलिए अबतक निकले निश्कर्ष के आधार पर कार्ययोजना बनानी है। ज्ञान तत्व विस्तार के लिए एक वर्ष का कार्यक्रम इस तरह बनाया जा रहा है कि

25 विशयों पर विचार मंथन को केन्द्रित किया जाए इनमें 12 विशय ऐसे हैं जो बौद्धिक ,राजनैतिक , आर्थिक संवैधानिक है उनकी सूची इस प्रकार है।

1. लोक स्वराज्य क्या, क्यो, और कैसे अथवा लोक स्वराज्य लोक तंत्र और तानाशाही।
2. भारतीय संविधान
3. वर्ग संघर्ष या वर्ग समन्वय
4. आर्थिक समस्याएँ और समाधान
5. अपराध और अपराध नियंत्रण
6. नई संवैधानिक व्यवस्था का स्वरूप
7. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार नियंत्रण
8. हमारी कर प्रणाली
9. महगाई यथार्थ या कल्पना
10. बेरोजगारी और समाधान
11. आतंकवाद कारण और निदान
12. पूंजीवाद साम्यवाद या समाजवाद

अन्य 13 ऐसे विशय चुने गए है जो सामाजिक ,पारिवारिक धार्मिक या भावनात्मक हैं वे विशय इस प्रकार हैं

1. भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप
2. आरक्षण कितना समाधान कितनी समस्या
3. महिला उत्पीडन कितना भ्रम कितना यथार्थ
4. संयुक्त परिवार प्रणाली
5. जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था
6. अहिंसा सिद्धांत या व्यवहार
7. विवाह पद्धति
8. व्यक्ति परिवार समाज के अधिकारों की सीमाएं
9. धर्म समाज और राज्य
10. मानव स्वभाव ताप बृद्धि
11. चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन
12. षोशित कौन
13. शिक्षा व्यवस्था राज्य की या समाज की

इन 25 विशयों पर विचार मंथन होगा लेकिन ज्ञान यज्ञ परिवार का अपना कोई निश्कर्ष नहीं होगा। ध्यान रखना होगा कि हम किसी विचार धारा का प्रचार प्रसार करने नहीं जा रहें है बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं की चिंतन शक्ति बढे ऐसा मार्ग बताने जा रहें हैं। ज्ञान यज्ञ परिवार ज्ञान तत्व विस्तार के लिए 6 दिशाओं में सक्रिय होगा।

1. साधना टी वी चैनल में एक सितम्बर से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे के करीब जिसका निश्चित समय बाद में बताया जाएगा, इन विशयों पर मेरा प्रवचन तथा प्रश्नोत्तर प्रसारित होगा।
2. एक बेवसाइड बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से ऐसे विशय समाज तक दिखाए जाएंगे।
3. ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका में बहुत तेजी से विस्तार किया जाएगा और उसमें विचार मंथन भी प्रकाशित होगा।
4. बडी मात्रा में सी.डी. बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा और अन्य कैसेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. प्रत्येक विशय पर पुस्तक भी तैयार होगी।
6. ज्ञान यज्ञ के माध्यम से या लोक स्वराज्य संवाद में शामिल होकर प्रत्यक्ष विचार मंथन होगा।

प्रयत्न किया जाएगा कि इन 6 माध्यम से अधिक से अधिक लोगों का ज्ञान तत्व बढे। छत्तीसगढ के सरगुजा संभाग में तो सघन ज्ञान यज्ञ अभियान चलाया जाएगा देश के अन्य भागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

मैने तो अपना सारा समय इस कार्य के लिए दिया ही हुआ है और भी कई लोग आंशिक समय देने के लिए तैयार हो रहे है। 29 एवं 30 अगस्त को आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस बैठक में शामिल हों जिससे सभी संगठनों का अलग-अलग ढाचा, कार्यक्रम, सक्रियता और सीमाएं स्पष्ट हो जाएं। मैं पुन इस कार्यक्रम के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ।

बजरंग मुनि